

श्रीमती कृष्णा कंवर ऊर्फ ठकुराईन

बनाम

राजस्थान राज्य

27 जनवरी, 2004

[दोराईस्वामी राजू एवं अरिजीत पासायत, न्यायाधीशगण]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-धारा 8, 21, 42(2) और 50-तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे में हेरोइन पाई गई -विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है-अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 42 (2), 50 और 57 की अनुपालना किया जाना - अभिनिर्धारित, अधिनियम की धारा 50 के तहत वांछित की जाने वाली सूचना संवहित करने का कोई विशिष्ट प्रारूप प्रावधित या आशित नहीं है-तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है -जिससे अभियुक्त को सही ढंग से दोषसिद्ध व दंडित किया गया।

अपीलार्थी-अभियुक्तों के वाहन को रोकने पर पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान उनके कब्जे में हेरोइन पाई गई। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अभियुक्त एम और एन से हेरोइन खरीदी और उन्हें बेचकर पैसे कमाए। इसके चलते पुलिस ने अभियुक्त एम और एन को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्तागण सहित सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध

आरोप सुनाए गए। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्तागण को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 और 21 के तहत दंडनीय अपराधों हेतु दोषी पाया एवं उन्हें 14 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये का अर्थदंड अदा करने विफल रहने के शर्त के साथ दंडित किया। अभियुक्त एम और एन को दोषमुक्त कर दिया गया। अपीलकर्तागण ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की। राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त एम और एन को दोषमुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक अपील भी दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थिगण एवं राज्य की अपीलों को खारिज किया गया। अतः अपीलार्थियों और राज्य की अपीलों। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलों के लंबित रहने के दौरान, एक अपीलार्थी की मृत्यु हो गई जिससे उसकी अपील को उपशमीप किया गया।

अपीलकर्तागण-अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42, 50 और 57 के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है क्योंकि इस संबंध हेतु किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य की कोई साक्ष्य नहीं दिया, जिन स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की गई, उन्होंने इस आधार पर अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया कि उन्होंने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे; कि कुछ निश्चित संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं जो एकत्र किए गए कथित नमूनों के

सुरक्षित प्रेषण के बारे में अभियोजन पक्ष के कथन को नष्ट करती हैं, जहां कि अभियुक्त एम और एन को दोषमुक्त किया जा चुका है, अपीलकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर की गई खरीद का स्रोत स्थापित नहीं किया गया है, और अपीलकर्ता के पास से बरामद हेरोइन काफी कम मात्रा में थी जिसके लिए सजा और जुर्माना बहुत अधिक है।

प्रत्यार्थी-राज्य ने तर्क दिया कि तीन उच्च पदस्थ अधिकारी तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में शामिल थे और अपीलकर्ता के पास उसे झूठा फंसाने का कोई भी कारण नहीं है, उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था और इसलिए अधिनियम की धारा 42 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ जैसा कि अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया है, अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन अपीलकर्ता को पुलिस अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में उसके विकल्प और पसंद के बारे में सूचित करके किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा विकल्प के प्रयोग पर, जैसा कि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है, कोई उल्लंघन नहीं है; रासायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि नमूने सीलबंध हालत में एवं मोहर व टैग बरकरार थे एवं उसकी जांच करने पर सामग्री हीरोइन पाई गई।

याचिकाओं को खारिज करने हेतु न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि -

अभिनिर्धारित- 1.1 ऐसा देखा गया है कि प्रदर्श. P-32 में वह गुप्त जानकारी है जो अभियोजन साक्ष्य संख्या-16 को प्राप्त हुई थी। कांस्टेबल अभियोजन साक्ष्य संख्या-9 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना दे दी थी। पुलिस अधीक्षक को लिफाफा सौंप दिया गया था। अभियोजन साक्ष्य संख्या-14 के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जांच की गई है और गवाहों द्वारा पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति की पुष्टि की गई। जिससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि उप-पुलिस अधीक्षक अभियोजन साक्ष्य संख्या-16. द्वारा भेजी गई सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसा होने पर, केवल इसलिए कि प्रेषण संख्या का विवरण नहीं बताया गया था, जिससे इस संबंध में परीक्षित गवाहान जिनके द्वारा दी गई साक्ष्य से प्रमाण स्थापित हुआ कि जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई थी, बाबत दी गई विश्वसनीयता साक्ष्य नष्ट नहीं होती है।[1108-बी, सी, डी]

1.2 विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42(2) का अनुपालन इस अर्थ में किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारी को भेजे गए थे। यद्यपि अपीलकर्ता ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भेजने के बारे में कोई

निश्चित सबूत नहीं था, फिर भी विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के विश्लेषण के मद्देनजर, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्बलता को प्रभावी ढंग से प्रमाणित नहीं किया गया है, इस न्यायालय को इस दलील में कोई दम नहीं लगता कि अधिनियम की धारा 42(2) का उल्लंघन हुआ है। [1111-बी, सी, डी]

पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह [1994] 3 SCC 299 और पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [1999] 6 SCC 172, का उल्लेख किया गया।

2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 50 के तहत दी जाने वाली आवश्यक जानकारी देने के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित या अभिप्रेत नहीं है। आवश्यक यह है कि अभियुक्त (संदिग्ध) को धारा में नामित अधिकारियों में से किसी एक की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। चूंकि कोई विशिष्ट तरीका या तरीका या तरीका निर्धारित या अभिप्रेत नहीं है, इसलिए न्यायालय को सार को देखना होगा न कि सूचना के रूप को। धारा 50 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के

तथ्यों पर किया जाना है और जिसके लिए व्यापक सामान्यीकरण या विशिष्ट प्रक्रियायुक्त सूत्र नहीं हो सकता है। अधिनियम की धारा 50 में कोई आत्म-दोषारोपण शामिल नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है जो किसी अभियुक्त (संदिग्ध) के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है और उसे किसी निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि बाद के चरण में अभियुक्त (संदिग्ध) यह दलील न दे कि वस्तुएं उसके पास रखवाई गई थीं या वह सामान उसके पास से बरामद नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो खोज की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। अधिनियम की धारा 50 वास्तव में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है जो विशेष रूप से कानून द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। एक उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है। अधिकार के अस्तित्व को बताने के लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है।[1112-A, B, 1113-G, H; 1114-A, B, C; 1115-C]

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [1999] 6 SCC 172; कलेमा तुंबा बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य JT (1999) 8 SC 293; गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2001] 3 SCC 28 रघबीर सिंह बनाम हरियाणा

राज्य, [1996] 2 SCC 201; प्रभा शंकर दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य,
(2003) AIR SCW 6592

और मदनलाल व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [2003] 6 SCC 382

3. बिना किसी कल्पना के बरामद की गई मात्रा छोटी है। इसके अलावा, कुछ भी नहीं दिखाया जा सका कि अधिनियम की धारा 57 का उल्लंघन कैसे हुआ। जब्त वस्तुओं और नमूनों की सुरक्षित अभिरक्षा ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित की गई है। रासायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चलता है कि नमूने सीलबंद स्थितियों में सील और टैग बरकरार रखते हुए प्राप्त किए गए थे। ऐसा होने पर, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई उल्लंघन नहीं है। जब ऊपर बताए गए कानूनी सिद्धांतों पर तथ्यात्मक स्थिति का परीक्षण किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह होता है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे अपना मामला स्थापित किया है और दोषसिद्ध और सजा उचित है। [1115-ई, एफ]

4. राज्य द्वारा बरी किए जाने पर सवाल उठाते हुए दायर की गई प्रति-अपील के संबंध में यह देखा गया है कि, अभियुक्त एम और एन के मामले में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उन्हें अपराध से जोड़ने के लिए सामग्री की कमी पाई। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा कि अधिनियम की धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। इन अभियुक्तों के घरों की तुरन्त तलाशी ली

गई। यहां तक कि अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं का भी कोई अनुपालन नहीं किया गया, हालांकि इसमें व्यक्तिगत तलाशी भी शामिल थी। तथाकथित खुलासा कथित तौर पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किया गया है। अधिनस्त न्यायालयों ने साक्ष्य को अपर्याप्त पाया है। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त एम और एन को बरी करने का निर्देश देना उचित समझती है।[1115-जी, एच; 1116-ए, बी]

आपराधिक अपीलीय न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 53/2003

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.02.2002 से, 1999 के सिंघल बेंच फौजदारी याचिका संख्या. 476 में के साथ

2003 का फौजदारी याचिका संख्या 52

फौजदारी याचिका संख्या 53/2003 में, राणा रंजीत सिंह, याचिकाकर्ता के लिए।

राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए अशोक के. महाजन के लिए मनीष सिंघवी।

फौजदारी याचिका संख्या 52/2003 में प्रत्यर्थागण के लिए श्रीमती के. शारदा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

अरिजित पासायत, न्यायाधीश -मूल रूप से इसके खिलाफ तीन अपीलें दायर की गई थी जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के सामान्य निर्णय से तीनों अपीलों का निपटारा कर दिया गया था। फौजदारी याचिका संख्या 51/2003 के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी शमसुद्दीन की मृत्यु हो गई और आदेश दिनांक 20/01/2004 द्वारा याचिका उपसमित मानते हुए निरस्त कर दी गई है। इसलिए, विचार अन्य दो याचिकाओं यानी आपराधिक याचिका संख्या 52/2003 और 53/2003 तक ही सीमित है।

दो अपीलों में से एक दोषी-अभियुक्त श्रीमती कृष्ण कंवर द्वारा दायर की गई है जो कि फौजदारी याचिका संख्या 53/2003 है और दूसरी अपील राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई है जो कि फौजदारी याचिका संख्या 52/2003 है, जिसमें अभियुक्त मांगी लाल और नाथू सिंह को बरी करने के फैसले पर सवाल उठाया गया है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने निर्देश दिया था और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा था। प्रारंभ में, सात व्यक्तियों को अभियुक्त व्यक्ति माना गया था। उनमें से चार, अर्थात्, शमशुद्दीन, श्रीमती कृष्ण कंवर, मांगी लाल और नाथू सिंह पर जिला एवं

सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने शमशुद्दीन और श्रीमती कृष्णा कंवर को अभियुक्त पाया और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 8 और 21 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया और जिसमें प्रत्येक को 14 साल के कठोर कारावास और चूंकि शर्तों के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा बेसर्त सुनाई गई। नाथू सिंह और मांगी लाल (ए-6 और ए-7) को क्रमशः बरी कर दिया गया।

मुकदमे के दौरान सामने आया कि अभियोजन मामला इस प्रकार है:

प्रसन्न कुमार खेमसारा (अभियोजन साक्ष्य संख्या-16), उप. पुलिस अधीक्षक, छोटी सादरी को दिनांक 5.7.1994 रात करीब साढ़े आठ बजे सूचना इस आशय से मिली कि दिनांक 6.7.1994 को प्रातः 5.00 बजे से 9.00 बजे के बीच शमशुद्दीन पुत्र शकूर खान, निवासी धाराखेड़ी, चित्तौड़गढ़ की ओर से राजदूत मोटरसाइकिल पर आएगा और प्रतिबंधित हेरोइन के साथ उदयपुर की ओर जाएगा।

उपरोक्त जानकारी न केवल दर्ज की गई बल्कि पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इंदरमल (अभियोजन साक्ष्य संख्या-9) के माध्यम से भी भेजी गई। उपरोक्त जानकारी पर, शिव प्रसाद (अभियोजन साक्ष्य संख्या-14), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, महिला कांस्टेबल श्रीमती विमला चौधरी (अभियोजन

साक्ष्य संख्या-5) और स्टाफ के अन्य सदस्य के साथ दिनांक 6.7.1994 को सुबह लगभग 4.00 बजे पुलिस स्टेशन, छोटी सादरी पहुंचे। राजीव दासोत, पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ दिनांक 6.7.1994 की सुबह घोमना चोराया पहुंचे, जहां दातर सिंह एस.एच.ओ. (अभियोजन साक्ष्य संख्या-11) सहित उनके पुलिस स्टेशन के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद उप. पुलिस अधीक्षक, प्रसन्न कुमार खमेसरा (अभियोजन साक्ष्य संख्या-16) ने घोमना चौराहे पर नाकाबंदी की, जिसमें युधिस्तर सिंह (अभियोजन साक्ष्य संख्या-8) और वर्दीचंद (अभियोजन साक्ष्य संख्या-13), स्वतंत्र गवाह भी शामिल थे।

सुबह करीब साढ़े छह बजे एक मोटरसाइकिल प्रतापगढ़ की ओर से आई, जिसे पुलिस दल ने पकड़ लिया। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने अपना नाम शमशुद्दीन बताया और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रीमती कृष्णा कंवर बताया। दोनों व्यक्तियों को गुप्त सूचना से अवगत कराया गया कि वे प्रतिबंधित हेरोइन ले जा रहे हैं और इसलिए, उनकी तलाशी ली जानी है, और, यदि वे चाहें, तो मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में भी तलाशी करवा सकते हैं। उन्हें लिखित नोटिस (क्रमशः प्रदर्श.P-9 और P-10) दिए गए थे, जिसके बाद वे दोनों

उप. पुलिस अधीक्षक, प्रसन्न कुमार खेमसारा (अभियोजन साक्ष्य संख्या-16) द्वारा स्वयं से तलाशी करवाना चाहा।

इसके बाद न केवल पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में बल्कि गवाहों युधिष्ठिर (अभियोजन साक्ष्य संख्या-8) और वर्दीचंद (अभियोजन साक्ष्य संख्या-13) की उपस्थिति में भी उनकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई। शमशुद्दीन के पेट और कमर पर प्लास्टिक की थैली बंधी हुई मिली जिसमें 2 कि.ग्रा. हेरोइन रखी हुई थी। इसी प्रकार, से,श्रीमती कृष्णा कंवर की व्यक्तिगत तलाशी में 600 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। उनके पास उपरोक्त प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने का कोई लाइसेंस नहीं था, इसलिए, समान जब्त कर लिया गया और 30 ग्राम के दो नमूने प्रत्येक लॉट से अलग-अलग निकाले गए और सील कर दिए गए। शेष माल-मुद्दा को भी अलग से सील कर दिया गया। जब्ती ज्ञापन, (प्रदर्श.P-3) एक साथ तैयार किया गया था, जिस पर न केवल दोनों अभियुक्तगण के अंगूठे का निशान लिया गया था, बल्कि प्रमाणक और पुलिस दल के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया गया, और ज्ञापन पर मोहर की छाप लगाई गई थी। सीलबंद सामान मालखाने में जमा करा दिया गया था।

पूछताछ करने पर, शमशुद्दीन ने एक खुलासा बयान (प्रदर्श.P-33) दिया और 33,000 रुपये के बारे में बताया, जो उसने हेरोइन और ऐसी कमाई से खरीदे गए अन्य घरेलू सामान बेचकर कमाए थे। इसके बाद,

शमशुद्दीन पुलिस पार्टी को अपने घर ग्राम बाटलगंज (यू.पी.) ले गए और गवाहों कन्हैया लाल और मगनी राम की उपस्थिति में 33,000 रुपये, एसबीबीजे शाखा, चेतक सर्किल, उदयपुर द्वारा जारी 30 मई, 1994 की 20,000 रुपये की एफडीआर बरामद की गई। अन्य घरेलू सामान और आभूषण भी प्रदर्श.P-5 के अनुसार बरामद किए गए।

शमशुद्दीन ने यह भी खुलासा किया कि दोनों आरोपियों से जब्त की गई प्रतिबंधित हेरोइन मांगी लाल और नाथू सिंह से खरीदी गई थी। इसके परिणामस्वरूप इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, और उनके प्रकटीकरण बयान पर, दिनांक 6.7.1994 को सायं 4.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उनके घरों की भी तलाशी ली गई। 27 ग्राम. हेरोइन मांगी लाल के घर से बरामद हुई और 225 ग्राम हेरोइन नाथू सिंह के घर से बरामद हुई थी। जब्ती ज्ञापन क्रमशः प्रदर्श.P-1 और P-2 तैयार किए गए। नाथू सिंह के घर से 41,980/-रूपये बरामद किये गये। अन्य आवश्यक ज्ञापन तैयार किये गये।

जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया और अपने बचाव को साबित करने हेतु सात गवाह परीक्षित कराए। विचारण न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाया, लेकिन मांगी लाल और नाथू सिंह को बरी कर दिया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें

पेश की। राज्य ने भी बरी किए जाने पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी और इसके अलावा अधिनियम की धारा 42, 50 और 57 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय इसमें कोई सार नहीं पाया और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। नाथू सिंह और मांगी लाल को बरी करने के फैसले पर सवाल उठाने वाली राजस्थान राज्य द्वारा दायर याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं थी।

श्रीमती कृष्ण कंवर द्वारा दायर याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह की गवाही प्रस्तुत नहीं की है। केवल सरकारी गवाहन ही परीक्षित करवाए गए। जिन स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की गई, उन्होंने अभियोजन पक्ष के कहानी का समर्थन नहीं किया एवं वास्तव में, यह कहा कि उन्होंने केवल कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे; जैसा कि दावा किया गया है, अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी 4.7.1994 को की गई थी, न कि 6.7.1994 को की थी। कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं जो कथित एकत्र किए गए नमूनों के सुरक्षित प्रेषण के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान को खराब करती हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष का मामला यह था

कि कथित प्रतिबंधित वस्तुएं मांगी लाल और नाथू सिंह से अभियुक्तगण शमशुद्दीन और श्रीमती कृष्ण कंवर द्वारा प्राप्त की गई थीं। मांगी लाल और नाथू सिंह को बरी कर दिया गया है, और इसलिए, आरोपियों द्वारा कथित तौर पर उपलब्ध करवाने के स्रोत को स्थापित नहीं किया गया है। श्रीमती कृष्ण कंवर से बरामदगी को बहुत बड़ी मात्रा नहीं कहा जा सकता, जैसा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने माना है। यह काफी कम मात्रा थी। अभियुक्त-अपीलार्थी की तलाशी के संबंध में साक्ष्य महिला कांस्टेबल (अभियोजन साक्ष्य संख्या-5) द्वारा श्रीमती कृष्ण कंवर का मामला भी विरोधाभासों से भरा है। उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यह काफी छोटी मात्रा थी। अवशिष्ट रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि 14 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना बहुत अधिक है।

इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने निर्णय और दोषसिद्धि का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि तीन उच्च पदस्थ अधिकारी तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में शामिल थे। इस बात का कोई कारण नहीं है कि वे अभियुक्त व्यक्तियों को गलत तरीके से फसाते हैं। अभियोजन साक्ष्य संख्या-16 ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, (अभियोजन साक्ष्य संख्या-14) की उपस्थिति में पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे, हालांकि उनसे गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की

गई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था, और इसलिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है, धारा 42 का कोई उल्लंघन नहीं है। धारा 50 की आवश्यकताओं का अनुपालन अभियुक्त को उसके विकल्प और पसंद और पुलिस अधिकारी (अभियोजन साक्ष्य संख्या-16) या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करके अनुपालना की गई थी। अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का विकल्प चुना। इसलिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई उल्लंघन नहीं है। जहां तक नमूनों का सवाल है, रासायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि नमूने सीलबंद प्राप्त हुए थे और टैग व मुहरें सही थे और विश्लेषण करने पर उनमें हेरोइन पाई गई।

यह देखा गया है कि प्रदर्श.P-32 में वह गुप्त जानकारी है जो उप-पुलिस अधीक्षक (अभियोजन साक्ष्य संख्या-16) को प्राप्त हुई थी। कांस्टेबल इंदरमल (अभियोजन साक्ष्य संख्या-9) ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दे दी थी। रात 9 बजे पुलिस अधीक्षक को और रात 11.00 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ एवं छोटी सादरी को लिफाफा सौंप दिया गया। उसी दिन सुबह करीब चार बजे वह थाने लौट आया। अतिरिक्त. पुलिस अधीक्षक की जांच अभियोजन साक्ष्य संख्या-14 के रूप में परीक्षित हुए हैं और

जिसमे उन्होंने पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति बाबत साक्ष्य दिए है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप-पुलिस अधीक्षक अभियोजन साक्ष्य संख्या-16 द्वारा भेजी गई सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसा होने पर, केवल इसलिए कि प्रेषण संख्या का विवरण नहीं बताया गया था, जिससे यह स्थापित करने के लिए जांच किए गए गवाहों के साक्ष्य की विश्वसनीयता नष्ट नहीं होगी कि जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई थी।

धारा 42 और 50 की अनुपालना की अपेक्षाओं पर एक संविधान पीठ द्वारा कई मामलों में निपटाया गया है, विशेष रूप से पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एससीसी 172 के मामले में। पैरा 17 में पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह (1994 (3) एससीसी 299 पैरा 25 पर) के पहले के फैसले के निष्कर्षों को उद्धृत किया गया और अनुमोदित किया गया। हम निष्कर्ष (2-सी) और (3) से चिंतित हैं जो इस प्रकार हैं:

"(2-सी) धारा 42(1) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास यदि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व सूचना दी गई है, तो उसे अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास व्यक्तिगत जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय IV के तहत अपराध किए गए हैं या ऐसी सामग्री जो ऐसे अपराधों के घटित होने

का प्रमाण दे सकती है, किसी इमारत आदि में छिपाई गई है, तो वह बिना वारंट के सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच गिरफ्तारी या तलाशी ले सकता है और यह प्रावधान यह अनिवार्य नहीं करता है कि उसे अपने विश्वास के कारणों को दर्ज करना चाहिए। लेकिन धारा 42(1) के प्रावधान के तहत यदि ऐसे अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ऐसी तलाशी करनी है, तो उसे अपने विश्वास के कारणों को दर्ज करना होगा।

(3) धारा 42(2) के तहत ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारी जो किसी भी जानकारी को लिखित रूप में लेते हैं या धारा 42(1) के प्रावधानों के तहत आधारों को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें तुरंत इसकी एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी चाहिए। यदि इस प्रावधान का पूरी तरह से अन-अनुपालन होता है तो इसका असर अभियोजन के मामले पर पड़ता है। उस सीमा तक यह अनिवार्य है। लेकिन अगर देरी हुई है तो क्या यह अनुचित था या इसे समझाया गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा।"

धारा 42 प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार है:

"42. वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति - (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार या सीमा सुरक्षा बल के किसी भी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) केंद्र सरकार या राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग के ऐसे किसी अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया है। राज्य सरकार, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी पर विश्वास करने का कारण है, कि किसी भी मादक पदार्थ, या मनोदैहिक पदार्थ के संबंध में जिसमें से अध्याय IV के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध किया गया हो या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में रखी या छिपाई गई हो -

(ए) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा;

(बी) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ दें और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को हटा दें;

(सी) ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां और कोई अन्य वस्तु और कोई जानवर या वाहन जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है और कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जिस पर उसके पास विश्वास करने का कारण है ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के घटित का सबूत प्रस्तुत कर सकता है; और

(डी) हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और, यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है:

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अपराधी के भागने के लिए सबूत या सुविधा छुपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अपने विश्वास के आधारों को दर्ज करने के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच। तो

वह किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत प्राप्त सूचना को लेखबद्ध करता है या उसके प्रावधान के तहत ऐसे विश्वास के कारण आधार दर्ज करता है, तो वह तुरंत उसकी एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा।

धारा 42, जैसा भी मामला हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकार प्राप्त कुछ अधिकारियों को बिना किसी वारंट या प्राधिकार के उल्लिखित उद्देश्य के लिए किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने में सक्षम बनाती है। धारा 42 "निर्माण, परिवहन या संलग्न स्थान" से संबंधित है जबकि धारा 43 सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 42 की उपधारा (1) के तहत अपनाई जाने वाली विधि और पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि संबंधित अधिकारी के पास व्यक्तिगत ज्ञान, या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी और लिखित रूप में ली गई जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि कोई नशीली दवाएं या पदार्थ जिसके संबंध में अधिनियम के अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई अन्य ऐसी वस्तुएँ जो ऐसे अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हैं, किसी "इमारत या

परिवहन या संलग्न स्थान" में रखी या छिपाई गई हैं, वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में बताए गए कार्यवाही कर सकता है।

यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार भागे हुए अपराधी के लिए साक्ष्य या सुविधा को छिपाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यह प्रावधान लागू हुआ, वह किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और अपने विश्वास के आधार पर दर्ज करने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच तलाशी ले सकता है। धारा 42 में दो घटक शामिल हैं। एक सूचना के आधार से संबंधित है अर्थात् (i) व्यक्तिगत ज्ञान से (ii) व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी। दूसरा यह है कि जानकारी अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध के घटित होने या किसी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान पर दस्तावेज़ या वस्तु को रखने या छुपाने से संबंधित होनी चाहिए जो ऐसे अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। जब तक दोनों घटक मौजूद न हों, धारा 42 का कोई प्रयोज्यता नहीं है। उप-धारा (2) आदेश देती है जैसा कि बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में उल्लेख किया गया था कि जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या प्रावधान के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह तुरंत उसकी

एक प्रतिलिपि अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज देगा। इसलिए, उप-धारा (2) केवल तभी लागू होती है जहां संबंधित अधिकारी किसी भी मामले में अधिकृत्य गणना करता है, यदि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या दस्तावेज आदि किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान पर छुपाए गए हैं। अतः कृत्य को अंजाम देना या दस्तावेज आदि को छुपाना किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान पर होना चाहिए।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा 42(2) का अनुपालन इस अर्थ में किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारी को भेजे गए थे। यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि वरिष्ठ अधिकारियों को अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां भेजने के बारे में कोई निश्चित सबूत नहीं था, फिर भी विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के विश्लेषण के मद्देनजर, जिसके साथ कोई नहीं किसी भी प्रकार की दुर्बलता को प्रभावी ढंग से प्रमाणित किया जा सकता है, हमें इस दलील में कोई तथ्य नहीं मिला कि धारा 42(2) का उल्लंघन हुआ है।

जहां तक धारा 50 के कथित अन-अनुपालन का सवाल है, उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

"50. शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। -

(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जा सके।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगा, अन्यथा निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।"

धारा 50 को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह दर्शित है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में ही लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। (देखें -कालेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (जेटी 1999 (8) एससी 293), बलदेव सिंह का मामला (सुप्रा), गुरबक्स सिंह बनाम

हरियाणा राज्य [2001] 3 एससीसी 28)। धारा 50 की भाषा स्पष्टतः रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा इस स्थिति को संदेह से परे तय किया गया था।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायालय ने संक्षेप में यह तय नहीं किया कि धारा 50 निर्देशिका थी या अनिवार्य प्रकृति की थी या नहीं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के प्रावधान निहित रूप से इसे अनिवार्य और बाध्यकारी बनाते हैं और जांच अधिकारी (सशक्त अधिकारी) पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालते हैं कि संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) की तलाशी धारा 50 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाए। व्यक्ति अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित किया जाता है कि यदि उसे इसकी आवश्यकता है, तो उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी और यदि वह ऐसा विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभियुक्त और अवैध वस्तुओं की बरामदगी को संदिग्ध बनाना और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को खराब करना। जहां केवल अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई

तलाशी के दौरान बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की गई है, यह अवैध था। आगे यह माना गया कि चूक इस तरह से मुकदमे को खराब नहीं कर सकती है, लेकिन अंतर्निहित पूर्वाग्रह के कारण जो एक अभियुक्त को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में सूचित करने में चूक के कारण होगा, इससे उसकी दोषसिद्धि और सजा अस्थिर हो जाएगी। निर्णय के पैराग्राफ 32 में (पृष्ठ 200 पर) इस स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। पैरा 57 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा गया:

"(1) कि जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या पूर्व सूचना पर कार्य करने वाला विधिवत अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अपने अधिकार के बारे में सूचित करना और तलाशी के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का कार्य अनिवार्य है। हालाँकि, ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से लिखित रूप में नहीं हो सकती है।

(2) किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता एक अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का कारण बनेगी।

(3) किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा, पूर्व सूचना पर, व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित किए बिना की गई तलाशी, यदि उसे इसकी आवश्यकता है, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के लिए ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसा विकल्प चुनता है, तो विफलता होगी। किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी लेने से मुकदमा तो खराब नहीं होगा लेकिन अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा दूषित हो जाएगी, जहाँ दोषसिद्धि केवल कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध वस्तु बरामद की गई।

(5) यह कि धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, यह अदालत द्वारा मुकदमे में दिए गए सबूतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उस मुद्दे पर किसी न किसी तरीके से निष्कर्ष निकालना दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का आदेश दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा। मुकदमे में अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना, कि धारा 50 के प्रावधानों और, विशेष रूप से, उसमें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत अनुपालन किया गया था, आपराधिक विचारण को न्यून करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(6) जिस संदर्भ में खोजे जाने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में संरक्षण को शामिल की गई है, हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं या निर्देशिका, लेकिन उस विफलता को मानते हैं संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उपधारा (1) से प्राप्त उसके अधिकार के बारे में सूचित करें और तस्करी के संदिग्ध की बरामदगी और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को कानून की नजर में खराब और विधी के तहत अस्थिर बनाएं।

(7) अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए संरक्षण उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त के पास से जब्त की गई अवैध वस्तु को अभियुक्त के अवैध कब्जे के सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हालांकि कोई अन्य सामग्री बरामद की गई है। उस तलाशी के दौरान, किसी अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामदगी के बावजूद, किसी अभियुक्त के खिलाफ अन्य कार्यवाहियों में अभियोजन पक्ष पर भरोसा किया जा सकता है।"

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली आवश्यक जानकारी देने के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित या इरादा नहीं है। आवश्यक यह है कि अभियुक्त (संदिग्ध) को इस धारा में नामित अधिकारियों में से किसी एक की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। चूंकि

कोई विशिष्ट तरीका या तरीका निर्धारित या इरादा नहीं है, इसलिए न्यायालय को सार को देखना होगा न कि सूचना के रूप को। क्या धारा 50 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना है और इसमें कोई व्यापक सामान्यीकरण या विशिष्ट प्रक्रियायुक्त सूत्र नहीं हो सकता है।

धारा 50 में कोई आत्म-दोषारोपण शामिल नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है जो किसी अभियुक्त (संदिग्ध) के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है और उसे किसी निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि बाद के चरण में अभियुक्त (संदिग्ध) यह दलील न दे कि सामान उस पर लगाया गया था या वह सामान उसके पास से बरामद नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो खोज की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996 (2) एससीसी 201), में धारा 50 का वास्तविक सार निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया था:

"8. जो प्रश्न हमें संदर्भित किया गया है उस पर 22.1.1996 को मनोहर लाल बनाम राजस्थान राज्य (सीआरएल.एमपी नं.138/96 एसएलपी (सीआरएल) संख्या 184/1996) में) में दो विद्वान न्यायाधीशों की

पीठ ने विचार किया था। हममें से एक (वर्मा, न्यायाधीश) ने बेंच की ओर से बोलते हुए कहा:

"स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को दिया गया विकल्प केवल यह चुनना है कि क्या वह तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा या निकटतम उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी या निकटतम उपलब्ध अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा। निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट का चयन तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अभियुक्त द्वारा।

9. हम पूर्वोक्त मनोहर लाल के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

10. किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुएं पाए जाने पर जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध हैं, उसे यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि वह इसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा था और यह उसे कठोर दंड के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसलिए, यह अधिनियम तलाशी लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। उसे किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है।

11. अधिनियम की धारा 50 के तहत विकल्प, जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है, केवल ऐसे वरिष्ठ अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का है। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का कोई और विकल्प नहीं है। धारा 50 में 'निकटतम' शब्द का प्रयोग प्रासंगिक है। तलाशी यथाशीघ्र की जानी चाहिए और, एक बार जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुनता है, तो यह पुलिस अधिकारी का काम है जिसे तलाशी लेनी है और जो भी व्यक्ति सुविधा से उपलब्ध है "राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट" उसकी उपस्थिति में तलाशी लेना है।

जैसा कि बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में उजागर किया गया है, यह देखा और परखा जाना चाहिए कि क्या धारा 50 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। वास्तव में धारा 50 अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है जो विशेष रूप से कानून द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। एक उचित, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है। अधिकार के अस्तित्व को व्यक्त के लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है। उचित, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है। अधिकार के अस्तित्व को बताने के लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को प्रभा शंकर दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003 AIR SCW 6592) में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया था।

मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003 (6) सुप्रीम 382) में भी इसी तरह के प्रश्न की जांच की गई थी।

बिना किसी कल्पना के बरामद की गई मात्रा छोटी है। इसके अलावा, कुछ भी नहीं दिखाया जा सका कि अधिनियम की धारा 57 का उल्लंघन कैसे हुआ। जब्त किए गए लेखों और नमूनों की सुरक्षित अभिरक्षा ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित की गई है। रासायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चलता है कि नमूने सीलबंद स्थितियों में सील और टैग के साथ प्राप्त किए गए थे। ऐसा होने पर, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई उल्लंघन नहीं है।

जब ऊपर बताए गए कानूनी सिद्धांतों पर तथ्यात्मक स्थिति का परीक्षण किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह होता है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे अपना मामला स्थापित किया है और दोषसिद्ध और सजा उचित है। श्रीमती कृष्णा कंवर द्वारा दायर अपील खारिज किया जाता है।

नाथू सिंह और मांगी लाल को बरी करने पर सवाल उठते हुए राजस्थान राज्य द्वारा दायर याचिका पर आते हुए, हमें यह पता चलता है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उन्हें अपराध से जोड़ने के

लिए सामग्री की कमी पाई। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा कि धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। इन आरोपियों के घरों की सीधे तलाशी ली गई। यहां तक कि धारा 50 की आवश्यकताओं का भी कोई अनुपालन नहीं हुआ, हालांकि इसमें व्यक्तिगत तलाशी भी शामिल थी। राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त द्वारा दी गई इतला के आधार पर, बरामदगी की गई थी जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 लागू होती है। तथाकथित खुलासा कथित तौर पर अभियुक्त शमशुद्दीन और श्रीमती कृष्ण कंवर द्वारा किया गया है। यहां भी विचारण न्यायालयों ने साक्ष्यों को अपर्याप्त पाया है।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई दुर्बलताओं के मद्देनजर, नाथू सिंह और मांगी लाल को बरी करने का निर्देश देना उचित था। उक्त याचिका निराधार है और खारिज की जाती है।

2003 की दोनों आपराधिक याचिका संख्या 52 और 53 तदनुसार खारिज की जाती हैं।

याचिकाएं खारिज की गईं।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **मदनलाल भाटी** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।